ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने ADEETIE योजना का शुभारंभ किया - यह योजना भारत में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को तेज़ी से बढ़ावा देने की पहल है

ADEETIE योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ : ₹1000 करोड़ की योजना, MSMEs को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने में सहायता प्रदान करेगी

पानीपत, 15 जुलाई, 2025 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु 'Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries & Establishments (ADEETIE)' योजना का आज हरियाणा के पानीपत स्थित आर्य (पी.जी.) कॉलेज में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह ऐतिहासिक पहल भारत की लो-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर एक निर्णायक कदम है।

₹1000 करोड़ के बजटीय प्रावधान वाली यह योजना विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, जिसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से MSMEs को ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहित करेगी। योजना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज सहायता, निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट (IGEA), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), और कार्यान्वयन के बाद निगरानी व सत्यापन (M&V) जैसे चरणबद्ध सहयोग शामिल हैं।

इस योजना के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 5% तथा मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा, जिससे MSMEs के लिए ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को अपनाना अधिक सुलभ और किफायती हो सकेगा।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ADEETIE पोर्टल (adeetie.beeindia.gov.in) का शुभारंभ किया और योजना पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने अपने मुख्य संबोधन में विकसित भारत की परिकल्पना के तहत ऊर्जा की भूमिका को रेखांकित किया और MSME क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर किया।

उन्होंने कहा कि "ADEETIE योजना के अंतर्गत प्रस्तावित तकनीकों से MSMEs में 30-50% तक ऊर्जा की बचत संभव है, जिससे पॉवर-टू-प्रोडक्ट अनुपात में सुधार होगा और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोरस

के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। **ADEETIE** योजना भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से **MSMEs** को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है। उपयुक्त प्रोत्साहन और सहायता तंत्र के माध्यम से हम स्वच्छ और कुशल तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं।”

श्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि औद्योगिक ऊर्जा दक्षता भारत की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल ने अपने संबोधन में **BEE** की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को पूरे औद्योगिक परिदृश्य में मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में 14 ऊर्जा गहन सेक्टर और 60 औद्योगिक क्लस्टर शामिल हैं। उन्होंने **MSMEs** को सशक्त करने हेतु एक मजबूत नीति और वित्तीय ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया।

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्री ए.के. सिंह ने अपने विशेष संबोधन में कोयला-आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को घटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने **MSMEs** से अपील की कि वे **ADEETIE** योजना में भाग लें और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सतत ऊर्जा समाधानों की ओर अग्रसर हों।

BEE के महानिदेशक एवं विद्युत् मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि यह योजना **MSMEs** को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें ₹1000 करोड़ के बजटीय प्रावधान में ₹875 करोड़ ब्याज सबवेंशन हेतु, ₹50 करोड़ ऊर्जा ऑडिट हेतु और ₹75 करोड़ कार्यान्वयन सहायता हेतु समर्पित हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना ₹9000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने की क्षमता रखती है, जिसमें **MSMEs** द्वारा संभावित ₹6750 करोड़ का उधारी निवेश शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा दक्षता भारत के निर्यात-उन्मुख औद्योगिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पंचायती राज, विकास, खान एवं भूविज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंतार, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा निदेशक श्रीमती प्रियंका सोनी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर कुछ **MSMEs** को प्रशंसा प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए, जिन्होंने योजना के पायलट चरण में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही प्रमुख औद्योगिक संघों के साथ **MoU** पर हस्ताक्षर किए गए। दो **MSME** प्रतिनिधियों ने ऊर्जा ऑडिट एवं तकनीक अपनाने के अपने अनुभव साझा किए, जिससे योजना की प्रारंभिक सफलता को दर्शाया गया।

कार्यक्रम का समापन **BEE** द्वारा धन्यवाद जापन के साथ हुआ।

उर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में:

भारत सरकार ने 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत उर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु नीतियों एवं रणनीतियों का निर्माण करना है, जो स्व-विनियमन और बाजार आधारित सिद्धांतों पर आधारित हो। BEE नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करता है।

परिशिष्ट: ADEETIE योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण

ब्याज सबवैशन सहायता:

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 5% तथा मीडियम एंटरप्राइजेस को 3% ब्याज अनुदान - ऊर्जा दक्ष तकनीकों के लिए लिए गए ऋण पर।

समग्र तकनीकी सहयोग:

ऊर्जा ऑडिट, DPR तैयारी, तकनीक पहचान और निगरानी व सत्यापन सहित संपूर्ण सहायता प्रणाली।

लक्ष्य क्षेत्र:

14 ऊर्जा गहन सेक्टर: पीतल, ईट, सेरामिक, रसायन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, फोर्जिंग, फाउंड्री, कांच, चमड़ा, कागज़, फार्मा, स्टील री-रोलिंग और वस्त्र उद्योग।

कार्यान्वयन की रणनीति:

पहले चरण में 60 औद्योगिक क्लस्टर और दूसरे चरण में अतिरिक्त 100 क्लस्टरों के साथ चरणबद्ध विस्तार।

कार्यान्वयन अवधि:

FY 2025-26 से FY 2027-28 तक तीन वर्षों में कार्यान्वयन, जिससे समयबद्ध परिणामों के आधार पर योजना का मूल्यांकन व विस्तार किया जा सकेगा।

बजट एवं संभावित प्रभाव:

कुल ₹1000 करोड़ का बजटीय प्रावधान:

₹875 करोड़ - ब्याज सबवैशन

₹50 करोड़ - ऊर्जा ऑडिट हेतु

₹75 करोड़ - BEE के माध्यम से सहायता

₹9000 करोड़ के निवेश को प्रेरित करने की क्षमता, जिसमें **₹6750** करोड़ **MSMEs** से संभावित ऋण निवेश।

पीआईबी चंडीगढ़/मंजीत